प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
07.02.2026 / प्रादेशिक समाचार / 11:00बजे

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए आर. आई.डी.एफ के तहत 7 सौ 58 करोड़ 81 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया है। वित्त वर्ष 2026–27 के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए शिमला में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागों से कहा कि आर.आई.डी.एफ. के तहत विधायकों की कोई डी.पी.आर. जिसे नाबार्ड को स्वीकृ ति के लिए प्रेषित की जा चुकी है और यदि वह डीपीआर किसी अन्य मद से स्वीकृत हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित विभाग उस डीपीआर को नाबार्ड से वापिस करने के लिए योजना विभाग को शीघ्र लिखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य में सुधार राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है और आने वाले दो वर्षों में 3 हजार करोड़ रुपये हाई–एंड टेक्नोलॉजी पर खर्च किए जाएंगे। इस बीच आज भी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विधायक प्राथमिकता की दूसरे दिन की बैठक आयोजित होंगी।

केंद्रीय बजट

केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश को राजस्व घाटा अनुदान का प्रावधान खत्म किए जाने पर प्रदेश सरकार की ओर से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव लोकभवन भेजा गया है। जानकारी के अनुसार राज्यपाल ने इसे अभी तक मंजूरी नहीं दी है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला

जिला संवाददाता

डिस्पैच : *विशेष सत्र के बजाय बजट सत्र बुलाने का सरकार को सुझाव दिया है जिसमें आर.जी.डी. के मुद्दे पर भी चर्चा की जा सकती है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया खुद शुक्रवार लोकभवन पहुंचे और विशेष सत्र के प्रस्ताव पर मंजूरी देने के लिए राज्यपाल से चर्चा की लेकिन राज्यपाल की ओर से बजट सत्र बुलाने का सुझाव दिया गया है। विपक्ष ने भी विशेष सत्र बुलाने के बजाय बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा किए जाने की बात कही है। ऐसे में अब सत्र को मंजूरी न मिलने से सरकार और लोकभवन के बीच खिंचाव बढ़ने के आसार हैं। वहीं आर.डी.जी. खत्म किए जाने पर सरकार ने कल रविवार को मंत्रिमंडल और सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा होगी। सरकार आर.जी.डी के मुद्दे पर विपक्ष का भी सहयोग मांग रही ताकि केंद्र सरकार पर बहाली के लिए दबाव बनाया जा सके। '52''आकाशवाणी शिमला के लिए मैं योगराज।*

राज्यपाल

नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले प्रदेश के एनसीसी कैडेटस ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से लोक भवन शिमला में भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कैडेटस को सम्मानित किया और राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल का प्रतिनिधित्व करने पर उन्हें बधाई दी। राज्यपाल से भेंट के

दौरान कैडेटस ने अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि राज्य के 21 एन.सी.सी. कैडेटस ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर अपनी प्रतिभा अनुशासन और समर्पण का प्रदर्शन किया है। उन्होंने इस वर्ष गणतंत्र दिवस शिविर में बालिका कैडेटस की संख्या अधिक होने पर खुशी जताई।

शी हाट

कांगड़ा जिला में श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम के समीप शी हाट का निर्माण किया जा रहा है। शी हाट में रेस्टोरेंट सहित अन्य पर्यटन गतिविधियों का संचालन महिलाओं द्वारा किया जाएगा। धर्मशाला के खंड विकास अधिकारी अभिनीत कात्यायन ने बताया कि इस भवन को शी हाट का नाम इसलिए दिया गया है, क्योंकि इसमें विभिन्न गतिविधियों का संचालन स्वयं सहायता समूहों, विलेज आर्गेनाजेशन और कलस्टर लेवल फेडरेशन की महिलाओं द्वारा किया जाएगा।

*ग्रामीण भण्डार को रैनोवेश किया जा रहा है रैनोवेश के उपरांत ही इसको शी हाट का नाम दिया गया है शी हाट का नाम इसलिए दिया गया यह जब पूरी बिल्डिंग बनकर तैयार होगी जब समय सहायत के समूह विलेज ऑग्रनाईजेशन की महिलाएं, और कलस्टर लेवल की महिलाए जो है वह इसको ऑपरेट करेंगी यह जिला कांगड़ा का पहला शी हॉट बनकर तैयार करने जा रहे है और यह एक माह शुरू करने जा रहे है और यह एक आटरेक्शन भी होगा श्रद्धालुओं के लिए माता का मंदिर भी बहुत नजदीक है यहां से।*

चैंपियनशिप

धर्मशाला स्थित केन्द्रीय विश्वविद्यालय को छठी बार आल इंडिया इंटर जोनल वुमन कबडडी चैंपियनशिप की मेजबानी करने का मौका मिला है। इस प्रतियोगिता का आयोजन धर्मशाला में 9 से 12 फरवरी तक किया जाएगा, जिसमें देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 2 सौ से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। केंन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफैसर सत प्रकाश बंसल ने एक पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल 9 फरवरी को उदघाटन समारोह में शिरकत करेंगे।

पी.एम.ए.वाई–जी–आवास

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन करोड़ 87 लाख से अधिक आवास की मंजूरी दी है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी ने राज्यसभा में बताया कि इस वर्ष 2 फरवरी तक दो करोड़ 95 लाख से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्ष में दो करोड़ 10 लाख 66 हजार से अधिक मकानों की मंजूरी दी गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय पहली अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका लक्ष्य मार्च 2029 तक चार करोड़ 95 लाख मकानों का नर्माण करना है।

इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे नमस्कार।